भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5760
जिसका उत्तर मंगलवार 03 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है

**विद्युत चालित वाहनों हेतु राजसहायता**

**5760. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विद्युत चालित वाहनों की खरीद संबंधी राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन शहरों के नाम क्या हैं, जहां विद्युत चालित वाहन चलाए जाने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार का गुजरात के बड़ौदा शहर में विद्युत चालित वाहन चलाए जाने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना हैं?

**उत्तर**
**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री**
**(श्री बाबुल सुप्रियो)**

**(क) से (घ):** सरकार ने 01 अप्रैल, 2015 से एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] तैयार की है जिसका उद्देश्य हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों, बाजार विकास तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र की सहायता करना है। इस योजना का चरण-I जो आरंभ में दिनांक 31.04.2017 तक था, को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया गया है।

मौजूदा फेम इंडिया स्कीम के तहत, व्यापक अंगीकरण को सुनिश्चित करने के लिए क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ताओं/उपभोक्ताओं) के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम तौर पर घटाए गए क्रय मूल्य के रूप में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवीज) के क्रय के लिए मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के **अनुबंध 13** में दिया गया है और जिसे समय-समय पर यथासंशोधित किया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

मौजूदा फेम इंडिया स्कीम निम्नलिखित चुनिंदा क्षेत्रों के लिए लागू है:-

1. "स्मार्ट सिटीज" प्रस्ताव के अंतर्गत आने वाले शहर।
2. प्रमुख मेट्रो आबादी समूह - दिल्ली एनसीआर, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद।
3. सभी राज्य राजधानियां और अन्य शहरी आबादी समूह/शहर, जिनकी आबादी 1 मिलियन से अधिक (2011 जनगणना के अनुसार) है।
4. पूर्वोत्तर राज्यों के शहर।

तथापि, सभी प्रकार के दुपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.2696(ई) दिनांक 30 सितम्बर, 2015 के द्वारा भारत में कहीं भी इनकी बिक्री के लिए स्कीम को लागू किया गया।

एक मिलियन से अधिक की आबादी वाला शहर होने के नाते गुजरात में वडोदरा शहर पहले ही इस स्कीम के अंतर्गत शामिल है।

*******